



दशहरे पर सीधी होती है गर्दन, सौभाग्यशाली भक्तों को होते हैं दर्शन

माँ कंकाली की टेढ़ी गर्दन का रहस्य

विश्व में कहीं नहीं ऐसा स्वरूप

पुजारियों और बुजुर्गों का मानना है कि माँ कंकाली का यह टेढ़ी गर्दन वाला स्वरूप पूरे विश्व में एक ही है। कहीं और माँ का ऐसा विग्रह नहीं है। पहले यहां पशु बलि की परंपरा थी, जिसे 1970 में बंद कर दिया गया। अब यहां केवल सात्विक पूजा और सच्चे मन से की गई प्रार्थना ही माँ को प्रसन्न करती है। भक्तों का अटूट विश्वास है कि जो भी सच्चे मन से माँ के इस दरबार में आता है, उसकी झोली कभी खाली नहीं जाती। माँ कंकाली की टेढ़ी गर्दन केवल एक मूर्ति की बनावट नहीं, बल्कि यह संदेश है कि माँ अपने भक्तों की पुकार सुनने के लिए हमेशा एक ओर झुकी रहती हैं।

400 साल पुराना आस्था का केंद्र

भोजपुर विधानसभा क्षेत्र के गुदावल गांव में स्थित यह मंदिर करीब 300 से 400 वर्ष पुराना बताया जाता है। मंदिर की स्थापना की कथा भी उतनी ही अलौकिक है। कहा जाता है कि हरलाल पटेल नाम के एक भक्त को सपने में माँ ने दर्शन दिए और जमीन के नीचे अपनी उपस्थिति का संकेत दिया। जब उस स्थान की खुदाई की गई, तो माँ की यह चमत्कारी प्रतिमा प्रकट हुई, जिसकी गर्दन टेढ़ी थी। तभी से यहां पूजा का सिलसिला शुरू हुआ, जो आज तक अनवरत जारी है। आज इस मंदिर का जनसहयोग से करीब सात करोड़ रुपये की लागत से भव्य निर्माण और विस्तार कराया जा रहा है। बहली भीड़ को देखते हुए प्रशासन और मंदिर समिति ने सुरक्षा, पार्किंग, ठहरने और भोजन-फलाहार की विशेष व्यवस्थाएं की हैं।

सीजेपी के सौरव दास-आशुतोष रांका को पांच दिन की न्यायिक हिरासत



नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: कांकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के नेता सौरव दास और आशुतोष रांका को दिल्ली की विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट अदालत ने पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दोनों पर जंतर-मंतर के उस क्षेत्र में कथित तौर पर बिना अनुमति प्रवेश करने और जमानत बांड की शर्तों का उल्लंघन करने का आरोप है, जिसे प्रदर्शन स्थल के रूप में अधिसूचना से हटा दिया गया है। दोनों को तिहाड़ जेल भेज दिया गया है।

सौरव दास, आशुतोष रांका और सीजेपी के एक अन्य नेता अजिंक्य शिंदे ने मंगलवार को कथित तौर पर बिना अनुमति प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश किया था। इसके बाद पुलिस ने तीनों को एहतियातन हिरासत में लिया। अदालत ने सौरव दास और

आशुतोष रांका को पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया, जबकि अजिंक्य शिंदे से जमानत बांड भरवाया गया। तीनों नेताओं की ओर से पेश अधिवक्ता अभिष्ट हेले ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पुलिस ने इस आशंका के आधार पर हिरासत की मांग की कि आरोपी कोई अपराध कर सकते हैं। वकील ने यह भी दावा किया कि पुलिस ने अदालत में तीनों पर लोगों को वहां आने के लिए बुलाने का आरोप लगाया, जबकि उन्होंने ऐसा कोई आह्वान नहीं किया था। अधिवक्ता ने जमानत बांड की शर्तों के उल्लंघन से भी इनकार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कर्नाट प्लेस से जुड़ी एक अलग शिकायत का इस्तेमाल इस मामले में किया गया।

अकिता भंडारी के माता-पिता से मिले राहुल-प्रियंका गांधी

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी बुधवार शाम इंडिया गेट पर घरना दे रहे अकिता भंडारी के माता-पिता से मिले। इस दौरान कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी भी उनके साथ मौजूद रही। अकिता के परिवार ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से दुय्धत कुमार गौतम की सिविकम के राज्यपाल पद पर नियुक्ति रद्द करने और

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की जांच पूरी होने तक इस पर रोक लगाने की अपील की है। परिवार का कहना है कि मामले की जांच पूरी होने तक ऐसी कोई नियुक्ति नहीं होनी चाहिए, जिससे जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठे। उन्होंने अकिता को न्याय दिलाने और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। अकिता भंडारी अंतराखंड के एक होटल में रिसोशनिस्ट के रूप में काम करती थीं। वर्ष 2022 में उनकी हत्या कर दी गई थी। मामले में सामने आए आरोपों के अनुसार, एक कथित वीडियो की विशेष सेवा देने से इनकार करने के बाद उनकी हत्या हुई थी। हालांकि, संबंधित वीडियो की पहचान सार्वजनिक रूप से स्पष्ट नहीं हो सकी है। अकिता का परिवार लंबे समय से दुय्धत कुमार गौतम को लेकर सवाल उठाता रहा है। परिवार की मांग है कि जांच पूरी होने तक उनकी नियुक्ति पर रोक लगाई जाए, ताकि जांच की निष्पक्षता को लेकर कोई संदेह न रहे।

त्योहारों के कारण इंडिया गठबंधन के मार्च पर विराम : राहुल

त्योहारों के मौसम को देखते हुए इंडिया गठबंधन ने दिल्ली में रोजाना होने वाले विरोध मार्च पर फिलहाल विराम लगा दिया है। हालांकि, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने स्पष्ट किया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के खिलाफ विपक्ष की लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि विपक्ष पीछे हटने वाला नहीं है और आगे की रणनीति पर काम चल रहा है। राहुल गांधी की ओर से बुलाई गई विपक्षी नेताओं की बैठक में नवगणि, दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ जैसे त्योहारों के कारण नियमित प्रदर्शन की व्यावहारिक दिक्कतों पर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक, अक्टूबर के तीसरे सप्ताह तक दिल्ली में रोजाना संयुक्त मार्च नहीं करने पर सहमति बनी है। हालांकि, अगले विरोध प्रदर्शन की तारीख और कार्यक्रम को लेकर कोई

आधिकारिक घोषणा नहीं की गई। बैठक के बाद राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष ने अपने आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए कई योजनाएं बनाई हैं। उन्होंने कहा, हमारी टीम रुकेगी नहीं। आज नहीं तो कल, परसों या तीन महीने बाद, हम लड़ाई के आखिर तक जाएंगे। उन्होंने जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल के रूप में अधिसूचना से हटाए जाने के फैसले को भी चुनौती देने की बात कही। इस बीच, विपक्षी दलों के वकील एसआईआर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर जल्द सुनवाई कराने का प्रयास कर रहे हैं। विपक्ष को उम्मीद है कि अदालत इस प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगाने पर विचार कर सकती है। बैठक में शामिल नेताओं ने एकजुटता बनाए रखने और आगे भी विरोध जारी रखने का संकल्प लिया। कांग्रेस की एक नवंबर को दिल्ली में प्रस्तावित रैली भी तय कार्यक्रम के अनुसार होगी।

सीजेपी को अमेरिका से फंडिंग मिलने का मैरी मिलबेन का दावा, अभिजीत का लिया नाम

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: अमेरिकी गायिका मैरी मिलबेन ने भारत में सीजेपी के विरोध प्रदर्शनों को लेकर अमेरिका से फंडिंग मिलने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पर साझा पोस्ट में उन्होंने अभिजीत दीपके का नाम लेते हुए दावा किया कि कुछ अमेरिकी दानदाता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बाधा डालने के लिए उन्हें आर्थिक मदद दे रहे हैं। हालांकि, इस दावे के समर्थन में कोई प्रमाण प्रस्तुत किए जाने की जानकारी नहीं है।

मैरी मिलबेन ने भारतीय युवाओं से सीजेपी के विरोध में आवाज उठाने की अपील भी की। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के 25 वर्षों के सार्वजनिक जीवन और लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का उल्लेख करते हुए उनके नेतृत्व का



समर्थन किया। गायिका ने आरोप लगाया कि कुछ दानदाता दुनिया के विभिन्न देशों में रूढ़िवादी विचारधारा वाले नेताओं को निशाना बनाते हैं। उनके मुताबिक,

ऐसे लोग संबंधित देशों के शिक्षित व्यक्तियों को अपने प्रभाव में लेकर उन्हें वापस भेजते हैं और विरोध प्रदर्शनों के लिए आर्थिक सहायता देते हैं। उन्होंने दावा किया कि इससे शासन और विकास पर असर पड़ता है।

मैरी मिलबेन ने सीजेपी के प्रदर्शनों के जवाब में शांतिपूर्ण जवाबी आंदोलन शुरू करने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि भारत में ही जन्मे और पले-बढ़े लोगों को इस विचारधारा का शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करना चाहिए। सीजेपी एसआईआर प्रक्रिया और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। अमेरिकी गायिका के आरोपों पर संबंधित पक्षों की प्रतिक्रिया की जानकारी उपलब्ध नहीं है।

सीजेपी का तिरंगा मार्च, 16 अक्टूबर को जुटने की अपील

नई दिल्ली। कांकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के नेताओं सौरव दास और आशुतोष रांका को पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद संगठन ने 16 अक्टूबर को देशभर में तिरंगा मार्च निकालने का ऐलान किया है। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने लोगों से शुक्रवार शाम पांच बजे दिल्ली के कर्नाट प्लेस स्थित सेंट्रल पार्क पहुंचने और तिरंगा लहराने की अपील की है। दीपके ने बुधवार शाम सोशल मीडिया मंच एक्स पर वीडियो साझा कर कहा कि सौरव दास और आशुतोष रांका को तिरंगा लहराने के कारण जेल भेजा गया है। उन्होंने लोगों से तिरों के साथ सेंट्रल पार्क पहुंचने का आग्रह करते हुए कहा कि तिरंगा लहराना अपराध नहीं है।

जयशंकर और कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद मिले

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने बुधवार को नई दिल्ली में कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की गई और व्यापार, निवेश, ऊर्जा, रक्षा, सुरक्षा, शिक्षा तथा लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ाने जैसे प्रमुख विषयों पर चर्चा हुई।

डॉ. जयशंकर ने मुलाकात की तस्वीरें साझा करते हुए कहा कि दोनों देशों ने विभिन्न क्षेत्रों में संबंधों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी विचारों का आदान-प्रदान हुआ। दोनों देशों के नेतृत्व के मार्गदर्शन और सरकार तथा उद्योग जगत के बीच



निरंतर संवाद के माध्यम से रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया। इससे पहले मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से फोन पर बातचीत की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत को सार्थक बताया हुए कहा कि दोनों देश भारत-कनाडा

संबंधों में बनी सकारात्मक गति को आगे बढ़ाने और रणनीतिक साझेदारी के प्रमुख क्षेत्रों में ठोस परिणाम हासिल करने के लिए मिलकर काम करने पर सहमत हुए हैं।

इन क्षेत्रों में व्यापार, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा और लोगों के बीच आपसी संबंध शामिल हैं।

ऑपरेशन सिंदूर से न्यूजीलैंड ने लिए सबक, भारत के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने की तैयारी

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: भारत के सैन्य अभियानों, विशेषकर ऑपरेशन सिंदूर, में न्यूजीलैंड ने रुचि दिखाई है। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने और सैन्य आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने की दिशा में बातचीत आगे बढ़ रही है। भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते के 20 अक्टूबर से लागू होने के साथ इस सहयोग को नई गति मिलने की संभावना जताई गई है। न्यूजीलैंड के भारत में पहले आवासीय रक्षा सलाहकार कमोडोर एंडी डार्जलिंग के अनुसार, दोनों देशों के बीच रक्षा संबंध अब संयुक्त नौसैनिक राश तक सीमित नहीं हैं। इनके दायरे में करीब 40 बिंदुओं वाला व्यापक सैन्य एजेंडा शामिल

हो गया है। डार्जलिंग ने सैन्य अभ्यास तरंग शक्ति में पर्यवेक्षक के रूप में हिस्सा लेने के बाद भारत के सैन्य अनुभवों का उल्लेख किया। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को आधुनिक युद्ध की प्रकृति समझने के लिएजाने से महत्वपूर्ण बताया। उनके अनुसार, इस अभियान से यह सीख मिली कि आधुनिक युद्ध में हवाई क्षेत्र बेहद व्यस्त और चुनौतीपूर्ण हो गया है। न्यूजीलैंड अब सैन्य अभ्यास के अगले संस्करण में पर्यवेक्षक के बजाय सक्रिय प्रतिभागी के रूप में शामिल होने की तैयारी भी कर रहा है। इससे दोनों देशों के बीच सैन्य प्रशिक्षण और रक्षा सहयोग बढ़ने की संभावनाएं हैं।

नईदुनिया ब्यूरो, काठमांडू: नेपाल संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) के वर्ष 2027-2029 के कार्यकाल के लिए सदस्य निर्वाचित हुआ है। न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में हुए चुनाव में नेपाल को महासभा में पड़े कुल 180 मतों में से 173 मत मिले। एशिया-प्रशांत क्षेत्रीय समूह से निर्वाचित देशों में नेपाल को सबसे अधिक मत प्राप्त हुए।

चुनाव के बाद न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र में नेपाल के स्थायी मिशन ने एक बयान जारी कर नेपाल को विश्वास और समर्थन देने वाले संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों के प्रति आभार व्यक्त किया। मिशन ने कहा, बहुपक्षवाद, मानवाधिकार, अंतरराष्ट्रीय कानून

और संयुक्त राष्ट्र को केंद्र में रखने वाली नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के प्रति नेपाल की प्रतिबद्धता पर विश्वास जताने के लिए हम संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं।

नेपाल ने मानवाधिकार परिषद के नए कार्यकाल के लिए निर्वाचित अन्य देशों को भी बधाई दी है। इनमें ब्राजील, बुरुंडी, डोमिनिकन गणराज्य, जर्मनी, घाना, आयरलैंड, जापान, जॉर्डन, कुवैत, मोल्दोवा, नाइजीरिया, यूक्रेन, उरुग्वे और जाम्बिया शामिल हैं।

नेपाल के स्थायी मिशन ने कहा कि वह संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों और अन्य साझेदारों के साथ निकट



सहयोग करते हुए मानव गरिमा की रक्षा, समावेशिता को बढ़ावा देने, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने तथा सभी के लिए समान और न्यायसंगत विकास को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।

नेपाल इससे पहले वर्ष 2018-2020 और 2021-2023 के दौरान लगातार दो कार्यकाल तक संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का

सदस्य रह चुका है। नए चुनाव के साथ नेपाल 1 जनवरी 2027 से तीसरी बार परिषद का सदस्य बनेगा।

वर्ष 2006 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, मानवाधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख अंतर-सरकारी निकाय है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के

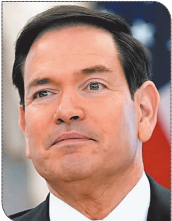
जिनेवा में स्थित है। परिषद में भौगोलिक प्रतिनिधित्व के आधार पर 47 सदस्य देश होते हैं, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा तीन वर्ष के कार्यकाल के लिए निर्वाचित करती है। परिषद सदस्य देशों में मानवाधिकारों की स्थिति की समीक्षा करती है, मानवाधिकार उल्लंघन से जुड़े मामलों पर चर्चा करती है और आवश्यक सिफारिशें जारी करती है। इसके अलावा, यह मानवाधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करती है। परिषद की सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा प्रक्रिया के तहत सभी सदस्य देशों में मानवाधिकारों की स्थिति का मूल्यांकन भी किया जाता है।

नेपाल का निर्वाचन अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मंच पर देश का प्रतिनिधित्व मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगा। परिषद के सदस्य के रूप में नेपाल मानवाधिकार, मानव गरिमा, समानता, समावेशिता, सामाजिक न्याय और अंतरराष्ट्रीय कानून के साथ नेपाल पर मानवाधिकारों से संबंधित अंतराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को लागू करने, मौलिक स्वतंत्रताओं की रक्षा करने और मानवाधिकारों के सार्वभौमिक मानकों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को व्यवहार में उतारने की जिम्मेदारी भी होगी।

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो अगले सप्ताह आएंगे भारत, ऊर्जा और व्यापार पर होगी चर्चा

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो अगले सप्ताह भारत दौरे पर आएंगे। इस दौरान वे मुंबई और गुजरात के जामनगर जाएंगे। यात्रा का उद्देश्य भारत और अमेरिका के बीच ऊर्जा सहयोग, रणनीतिक साझेदारी और व्यापारिक संबंधों को मजबूत करना है। इस दौरान रुबियो वरिष्ठ भारतीय अधिकारियों और प्रमुख कारोबारी प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। भारत आने से पहले रुबियो उज्बेकिस्तान के समरकंद जाएंगे। वहां वे पांच मध्य एशियाई देशों के साथ होने वाली सी5+1 मंत्रिस्तरीय बैठक में हिस्सा लेंगे। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार तथा भारत की ओर से रूस से तेल खरीदने को लेकर मतभेद

बने हुए हैं। इसके बावजूद अमेरिका दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को आगे बढ़ाना चाहता है। मई के बाद यह रुबियो का दूसरा भारत दौरा होगा। इससे पहले उन्होंने नई दिल्ली में आयोजित काउड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया था। उस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर से मुलाकात की थी। हाल ही में विदेश मंत्री जयशंकर ने ब्लूमिंगटन न्यू इकोनॉमी फोरम में कहा था कि भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता किसी नतीजे की ओर बढ़ रही है। उन्होंने बदलते वैश्विक व्यापार परिदृश्य के बीच अमेरिका के साथ संबंधों का पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया था।



दिल्ली प्रदर्शन पर संयुक्त राष्ट्र की टिप्पणी अनुचित

भारत ने कहा- आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं

दिल्ली में विरोध प्रदर्शन को लेकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय की टिप्पणी पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इसे अनुचित और अस्वीकार्य बताया हुए कहा कि ऐसी टिप्पणियां भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के समान हैं। जायसवाल ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय का रवैया चुनिंदा प्रतीत होता है। उनके अनुसार, दुनिया के अन्य हिस्सों में विरोध प्रदर्शनों और कानून लागू करने वाली एजेंसियों की कार्रवाई पर संगठन ने अपने सार्वजनिक बयानों में ऐसी ही प्रतिक्रिया नहीं दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने चेतावनी दी कि इस तरह



के रवैसे से बहुपक्षवाद में लोगों का विश्वास कम हो सकता है। साथ ही, इससे संबंधित संगठन की विश्वसनीयता भी प्रभावित होगी। इस बीच, जायसवाल ने बिस्मटेक देशों के गृह मंत्रियों की बैठक के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारत के गृह मंत्री ने बैठक को मेजबानी की और बिस्मटेक के सभी सदस्य देशों ने इसमें भाग लिया। बैठक के बाद दिल्ली घोषणा को स्वीकार किया गया। इसके तहत सदस्य देशों ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई। सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों में आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई, मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक और धनशोधन के विरुद्ध संयुक्त प्रयास शामिल हैं।

एसआईआर प्रक्रिया को चुनौती देने सुप्रीम कोर्ट पहुंचे ओवैसी, तत्काल रोक की मांग

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: एआईएमआईएम अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने चुनाव आयोग की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। बुधवार को दाखिल याचिका में उन्होंने प्रक्रिया के तरीके पर सवाल उठाते हुए इसे तत्काल रोकने की मांग की। इससे पहले लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरेगे और अन्य विपक्षी नेताओं ने भी एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। उन्होंने मतदाता सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया में कथित

गड़बड़ियों का आरोप लगाते हुए मतदाता आंकड़ों और नाम हटाने की प्रक्रिया के स्वतंत्र ऑडिट की मांग की है। विपक्षी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में समिति गठित करने का प्रस्ताव भी रखा है। समिति से एसआईआर प्रक्रिया के क्रियान्वयन और मतदाता सूची तथा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से जुड़े तकनीकी तंत्र की जांच कराने की मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं ने यह सवाल भी उठाया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने अन्य चुनाव आयुक्तों की जानकारी या सहमति के बिना आयोग की सामूहिक शक्तियों का इस्तेमाल कैसे किया। उन्होंने



देशभर में एसआईआर लागू करने से जुड़े दस्तावेज, बैठक का विवरण, फाइलें, टिप्पणियां और आपत्तियां उपलब्ध कराने की मांग की है।

एसीपी की शिकायत पर पत्रकार समेत तीन पर एफआईआर

नई दिल्ली। दिल्ली में एसआईआर प्रदर्शन के दौरान सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) विवेक भगत पर कथित जातिस्मृचक और अपमानजनक टिप्पणी करने का मामला सामने आया है। उनकी शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने संसद मार्ग थाने में पत्रकार समेत तीन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। मामले में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धाराएं भी लगाई गई हैं। घटना 3 अक्टूबर को बुटा सिंह गोलचक्कर पर हुई थी। उस समय नई दिल्ली जिले के कर्नाट प्लेस उपमंडल में तेनात एसीपी विवेक भगत कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए इड्यूटी पर थे। शिकायत में भगत ने बताया कि वह अनुसूचित जाति समुदाय से आते हैं।

